



राहुल भी उस सुविधा के आरामदेह जाल में फंस गये हैं, जिसमें सोनिया गांधी फंसी थीं

सोनिया गांधी सदा इस बात से बचती थीं , कि पार्टी अपनी हार के कारणों पर गंभीरता से बहस करे, और यह तय हो कि, हार के लिये जिम्मेवार कौन था

जो मुद्दे हैं उन्हें पार्टी नेतृत्व के साथ उठाना है

वंदे मातरम के दौरान भी सीधे खड़ा होना पड़ेगा

केन्द्र सरकार राष्ट्र गीत वंदे मातरम को राष्ट्र गान जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी में है

- श्रीनंद झा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 24 जनवरी। क्या भारत के राष्ट्र गीत को राष्ट्रीय गान के समान दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए?

इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” को राष्ट्र गान के समान सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक विधिवत प्रस्ताव तैयार करना था।

वर्तमान समय में, दोनों गीतों के लिए कानूनी और अनिवार्य प्रोटोकॉल में एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। उदाहरण के लिए, जब राष्ट्र गान बजाया जाता है तो खड़ा होना अनिवार्य है और ऐसा न करने या इनकार करने पर “प्रीवेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स नेशनल ऑनर एक्ट, 1971” के तहत दंड का प्रावधान है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय गीत के बजने पर खड़ा होना अनिवार्य बनाने वाला कोई लिखित नियम या कानूनी बाध्यता फिलहाल मौजूद नहीं है।

वंदे मातरम् पर भाजपा सरकार का नया जोर आगामी विधानसभा चुनावों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, हिंदू मतों के एकीकरण की पार्टी की राजनीतिक रणनीति के अनुरूप देखा जा रहा है। इस गीत को लेकर ऐतिहासिक, धार्मिक और

राष्ट्र गान जन गण मन जब बजाया जा रहा हो तब खड़े होना अनिवार्य है और इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया है, पर वंदे मातरम में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। केन्द्र सरकार वंदे मातरम को भी राष्ट्र गान, जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी में है।

इस सम्बध में गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। चर्चा है कि भाजपा सरकार बंगाल चुनावों के मद्देनजर वंदे मातरम के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और इस आधार पर वोटों के धुवीकरण की उम्मीद कर रही है।

राजनीतिक व्याख्याओं से जुड़े विवाद लंबे समय से रहे हैं। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उनके उपन्यास “आनंद मठ” से लिया गया है और इसमें कुल छह अंतरे (स्टैन्जा) हैं, जिनमें हिंदू देवी की छवियां शामिल हैं। पार्टी के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 की बैठक में केवल पहले दो अंतरों के प्रयोग का निर्णय लिया था, क्योंकि बाद के अंतरे मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को अलग-थलग कर सकते थे।

यह विवाद पिछले वर्ष गीत की 150वीं वर्षगांठ पर फिर से उभरा, जब

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तर्क दिया कि कांग्रेस द्वारा गीत को संक्षिप्त किए जाने का देश के विभाजन में योगदान रहा। कांग्रेस ने इस निर्णय का बचाव करते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया। कुछ मुस्लिम विद्वानों, जैसे मौलाना अरशद मदनवी, ने कहा है कि वे राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं, लेकिन, एकेश्वरवाद से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण, इसके सामूहिक गायन में भाग नहीं ले सकते।

1905-08 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान “वंदे मातरम्” एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुरानों पर संदेह है और नयों पर भरोसा नहीं हो रहा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना के उच्च पदों पर तैनात अपने पुराने साथियों को हटा रहे हैं, पर उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। चीन ने अपने सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को हटा दिया है। यह कदम राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा चलाए जा रहे उस कठोर अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उन सभी लोगों को हटाया जा रहा है, जो राजनीतिक रूप से या सत्ता के लिहाज से उनके संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं।

जनरल झांग योडशिया, जो अब तक चीन के अत्यंत शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमिशन (सी.एम.सी.) के उपाध्यक्ष थे, को हटाए जाने के बाद इस सात सदस्यीय शीर्ष सैन्य संस्था में अब केवल एक ही अन्य सदस्य बचा है। यही संस्था चीन की विशाल सेना को नियंत्रित करती है।

शी जिनपिंग ने एक के बाद एक

हाल ही में शी ने अपने पुराने साथी और बेहद वफादार रहे जनरल झांग को पद से हटा दिया, वे चीन के सर्वशक्तिमान सेंट्रल मिलिटरी कमिशन के वाइस चेयरमैन थे।

जनरल झांग और शी की राजनैतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी थी इसीलिए जनरल झांग शी के बेहद विश्वासपात्र बन गए। लेकिन शी ने भ्रष्टाचार के संदेह में जनरल झांग को हटा दिया है।

असल में शी ज़िनपिंग ने चीन की सेना का शुद्धिकरण शुरू किया है, क्योंकि, भारी भ्रष्टाचार की खबरें मिल रही थीं पर इससे सेना के उच्चस्तर पर एक खालीपन सा आ गया है।

सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। लगातार चल रही इन कार्रवाहियों में कई शीर्ष

सैन्य कमांडरों को पद से हटाकर जेल या हिरासत शिविरों में भेजा गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

थरुर ने कैनडा के प्र.मंत्री की चेतावनी का समर्थन किया

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 24 जनवरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को सुझाव दिया कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में भारत को कैनडा के प्रधानमंत्री की ‘जीवित बने

थरुर ने कहा, आज विश्व की व्यवस्था जिसकी लाठी उसकी भैंस पर आधारित है, नियम टूटते जा रहे हैं। भारत को भी कैनडा के प्र.मंत्री की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।

रहने’ की अपील से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस सप्ताह दावोस की बर्फीली पृष्ठभूमि में कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐसा भाषण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ 10 साल में ए.आई. के उपयोग से भारत की आय में 45 लाख करोड़ रुपये का इजाफा होगा’

जानी मानी कॉरपोरेट सलाहकार व “चारटर्ड एकाउन्टैंट” कम्पनी प्राइस वॉटर हाउस (पी.डब्ल्यू.सी.) का यह आंकलन भारत के लिये बहुत उत्साह वर्धक है

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स (पी.डब्ल्यू.सी.) इंडिया ने एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई) फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसका अनुमान है कि यह टेक्नॉलजी, सन् 2035 तक, पांच मुख्य सेक्टर्स में, नॉर्मलन कीमतों पर भारत के लिए लगभग 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 45 लाख करोड़ रुपये) का अतिरिक्त आर्थिक मूल्य पैदा कर सकती है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, यह देखते हुए कि खर्च के मामले में भारत के सालाना बजट का आकार 50 लाख करोड़ रुपये है।

आंकड़ों से आगे, फर्म का तर्क है कि भारत के पास न केवल बड़े पैमाने पर ए.आई को लागू करने का, बल्कि

इस आंकलन का पूरा महत्व समझने के लिये यह जानना जरूरी है, कि देश के बजट में खर्च का आंकड़ा वर्तमान में कुल 50 लाख करोड़ है।

“इन्क्लूसिव ए.आई.” का एक विश्व स्तर पर विशिष्ट मॉडल बनाने का दुर्लभ अवसर है, एक ऐसा मॉडल जो उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ समाज के हर वर्ग पर सकरात्मक असर डाले।

पी.डब्ल्यू.सी. के अनुसार, अनुमानित आर्थिक लाभ का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल से आएगा, ये ऐसे सेक्टर्स हैं, जो मिलकर लाखों भारतीयों को रोजगार देते हैं और देश के विकास और प्रगति को चुनौती के केन्द्र में हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पिछली लहरों के विपरीत, जो मुख्य रूप से सेवाओं और

मौसम की जानकारी और स्थानीय मिट्टी की जानकारी शामिल होगी, खेती की पैदावार बढ़ा सकती है, इनपुट की बर्बादी कम कर सकती है और छोटे किसानों के लिए आय को स्थिर कर सकती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक कमजोरी है।

हेल्थकेयर को एक और बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है। पी.डब्ल्यू.सी. भारत में डॉक्टरों और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पुरानी कमी को दूर करने के तरीके के रूप में ए.आई. आधारित जांच प्रणाली, मरीजों की प्राथमिक जांच और दूरस्थ इलाज मॉडल भारत में डॉक्टरों और स्वास्थ्य ढांचे की कमी को कम करने में मदद कर सकती है। यदि जिम्मेदारी से लागू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वर्षा के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण नहीं घटा

नयी दिल्ली, 24 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को हुई बारिश और तापमान में गिरावट के बावजूद शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब श्रेणी में बनी रही।

■ शहर के कुछ इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शहर के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है।

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई खराब श्रेणी में रहा, जिसमें सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) की अधिकता देखी गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण तापमान में तो कमी आई है लेकिन प्रदूषण के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)